AGRASEN CIVIL SERVICES ACADEMY

Where tradition meets innovation

ACSA

22 से 31 मई 2023

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स

For

UPSC / RPSC EXAMS

and All Other Competitive

- त्रई करेगा स्क्वैश वर्ल्ड कप की मेजबानी
- महाराणा प्रताप लोक
- पंच कर्म संकल्प
- जीआरएसई की 'GAINS ' स्टार्टअप चुनौती
- रय्याना बरनावी
- हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय
- एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन 2023
- 75 रुपये का स्मारक सिक्का

A UNIT OF
AGRAWAL PG COLLEGE
Affiliated to University of Rajasthan | Managed by Shri Agrawal Shiksha Samiti
(A Co-Educational College)

+91-8824395504, +91-8290664069
www.acsajaipur.com
Agrasen Katla, Maharaja Agrasen Marg,
Agra Road, Jaipur - 302003

Current Affairs 22 May to 31 May 2023

Brief:-

- चेन्नई करेगा स्क्वैश वर्ल्ड कप की मेजबानी :
- महाराणा प्रताप लोक
- शवोत क्या है?
- पंच कर्म संकल्प :
- जीआरएसई की 'GAINS ' स्टार्टअप चुनौती
- रय्याना बरनावी
- हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय
- एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन 2023
- अनुच्छेद 239AA क्या है?
- यूक्रेन संघर्ष में बखमुत
- ई-अपील योजना 2023
- नमो शेतकरी महासंमान योजना
- इराक के विकास का मार्ग
- नया संसद भवन
- 75 रुपये का स्मारक सिक्का

चेन्नई करेगा स्क्वैश वर्ल्ड कप की मेजबानी :

चेन्नई शहर प्रत्याशा से लबरेज है क्योंकि यह बहुप्रतीक्षित 2023 स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन (डब्ल्यूएसएफ) के साथ साझेदारी में तमिलनाडु के खेल विकास प्राधिकरण (एसडीएटी) द्वारा आयोजित यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम, प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले दुनिया के शीर्ष स्क्वैश खिलाड़ियों का प्रदर्शन करेगा।

13 से 17 जून तक, चेन्नई के स्क्वैश उत्साही दो प्रमुख स्थानों - एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल और इंडियन स्क्वैश एंड ट्रायथलॉन अकादमी (आईएसटीए) में गहन मैच देखेंगे। ये अत्याधुनिक सुविधाएं इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं और खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों के लिए एक शानदार अनुभव प्रदान करती हैं।

ऐस खिलाड़ी भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं ,भारतीय टीम में दो असाधारण खिलाड़ी हैं जो टूर्नामेंट में अपने अभियान की अगुआई करेंगे। सौरव घोषाल, जो वर्तमान में दुनिया में 19वें स्थान पर हैं, कोर्ट पर अपने जबरदस्त कौशल और अनुभव को लेकर आए हैं। उनके साथ 19 बार की नेशनल चैंपियन जोशना चिनप्पा भी शामिल हैं, जिनके कौशल ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इन दो दिग्गज एथलीटों के नेतृत्व में भारतीय दल विश्व मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है।

प्रायोजन और इतिहास

2023 स्क्वैश विश्व कप को तमिलनाडु सरकार से समर्थन मिला है, इस क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। यह पहली बार नहीं है जब चेन्नई ने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी की है। 2011 में, शहर ने अपनी समृद्ध स्क्वैश विरासत को जोड़ते हुए विश्व कप के पिछले संस्करण को देखा।

स्क्वैश विश्व कप का विकास

स्क्वैश विश्व कप में 2011 में अपने अंतिम चरण के बाद से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। टूर्नामेंट अब टीमों के भीतर लैंगिक समानता को प्राथमिकता देता है, स्क्वैश में समावेशिता और समानता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, मैच 5 खेलों से लेकर सात अंकों तक खेले जाएंगे, प्रतियोगिता में एक रोमांचक मोड़ लाया जाएगा और खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए तीव्रता के स्तर को समान रूप से बढ़ाया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता

2023 स्क्वैश विश्व कप ट्रॉफी के लिए कुल आठ देश प्रतिस्पर्धा करेंगे। मेजबान देश भारत के अलावा, हांगकांग, चीन की टीमें; जापान; मलेशिया; मिस्र; दक्षिण अफ्रीका; ऑस्ट्रेलिया; और कोलंबिया एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। अपने दुर्जेय स्क्वैश खिलाड़ियों के लिए जाने जाने वाले मिस्र के शीर्ष वरीयता प्राप्त होने की उम्मीद है, जो पूरे टूर्नामेंट में रोमांचक मुकाबलों के लिए मंच तैयार करेगा।

महाराणा प्रताप लोक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में भोपाल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक के निर्माण की घोषणा की।

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक: शौर्य को श्रद्धांजलि

भोपाल में आगामी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक महाराणा प्रताप की विरासत के लिए एक वसीयतनामा के रूप में काम करेगा। इस स्मारक का उद्देश्य उनके बलिदान, तपस्या, संघर्ष और वीरता सहित उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करना है। उनकी उल्लेखनीय यात्रा के सार को पकड़कर, आने वाली पीढ़ियां अपने लोगों की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों की सराहना करने और उनसे सीखने में सक्षम होंगी।

महाराणा प्रताप और सहयोगियों का चित्रण

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक में महाराणा प्रताप के सात सहयोगियों भामाशाह, पंजाबिल, चेतक आदि के योगदान को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। यह चित्रण महाराणा प्रताप की न्याय और स्वतंत्रता की खोज में उनकी भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए इन व्यक्तियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को उजागर करेगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि महाराणा प्रताप की वीरता और पराक्रम को भुलाया न जाए, राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में उनकी प्रेरक कहानियों को शामिल किया जाएगा। इन शैक्षिक पहलों के माध्यम से, छात्रों को उनके साहसी कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य भावना के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इन मूल्यों को स्थापित करके, पाठ्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में महाराणा प्रताप के लिए गर्व और प्रशंसा की भावना का पोषण करना है।

महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड की स्थापना

महाराणा प्रताप के योगदान के महत्व को स्वीकार करते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड की स्थापना करने की योजना बनाई है। यह बोर्ड महाराणा प्रताप के मूल्यों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी विरासत लोगों के दिलों और दिमाग में जीवित रहे। विभिन्न पहलों के माध्यम से, बोर्ड उनके साहस, देशभक्ति और लचीलेपन के सिद्धांतों का जश्न मनाने और प्रचार करने का प्रयास करेगा।

महाराणा प्रताप की विरासत

महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह सम्मानित सिसोदिया वंश से संबंधित थे और अकबर और मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनके प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। हल्दीघाटी की लड़ाई, अन्य प्रमुख

लड़ाइयों में, अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण है। गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से महाराणा प्रताप के सैन्य प्रतिरोध ने बाद के विद्रोहियों के लिए एक प्रेरणा का काम किया, जिसमें मलिक अंबर और शिवाजी जैसे उल्लेखनीय व्यक्ति शामिल थे।

शवोत क्या है?

शवोत, जिसे सप्ताहों के पर्व के रूप में भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण यहूदी त्योहार है जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। फसह के दूसरे दिन के ठीक 50 दिन या सात सप्ताह बाद मनाया जाता है, शावोत सिनाई पर्वत पर टोरा देने और पहले फल की फसल की याद दिलाता है।

शवोत टोरा की प्रस्तुति की महत्वपूर्ण घटना के आसपास केंद्रित है। यहूदी परंपरा के अनुसार, इस्राएलियों को मिस्र में गुलामी से मुक्त करने के बाद, वे रेगिस्तान से यात्रा करते हुए सिनाई पर्वत पर पहुंचे। यह इस पवित्र स्थल पर था कि मूसा ने टोरा को सीधे भगवान से प्राप्त किया, जिसमें दस आज्ञाएं और अन्य शिक्षाएं शामिल थीं जो यहूदी कानून और नैतिकता की नींव बनाती हैं।

टिक्कुन लील शवोत: रात भर चलने वाला तोराह अध्ययन

शवोत का एक अभिन्न अंग टिक्कुन लील शावोत की परंपरा है, जो एक रात का तोराह अध्ययन है। प्रतिभागी टोरा की शिक्षाओं पर गहन अध्ययन और चिंतन में संलग्न होते हैं, इसके ज्ञान को प्राप्त करने और सीखने की अपनी उत्सुकता का प्रदर्शन करते हैं। यह अध्ययन सत्र यहूदी विरासत से गहरे संबंध को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत और सांप्रदायिक आध्यात्मिक विकास की सुविधा प्रदान करता है।

डेयरी उत्पाद: प्रचुरता का प्रतीक

शवोत का एक अनूठा पहलू डेयरी उत्पादों की खपत है। यह परंपरा इज़राइल की भूमि और इसकी समृद्ध कृषि उपज की प्रचुरता का प्रतीक है। त्योहार के दौरान चीज़केक, ब्लिंट्ज़ और अन्य डेयरी व्यंजनों का आनंद लिया जाता है, जो व्यक्तियों को समृद्धि और आशीर्वाद की याद दिलाता है।

हार्वेस्ट सीजन और कृषि महत्व

शावोत फसल के मौसम के साथ मेल खाता है, जो इसके कृषि महत्व को दर्शाता है। प्राचीन समय में, यहूदी भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यरूशलेम के मंदिर में अपना पहला फल चढ़ाते थे। कृषि आशीर्वाद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शवौत के दौरान भूमि और इसकी भरपूर उपज के लिए यह संबंध जारी है।

फूलों और हरियाली का प्रतीक

शवोत पर, घरों और सभास्थलों को खिलने और सब्ज़ तत्वों से सजाया जाता है। यह अधिनियम वसंत की फसल के बाद भूमि के खिलने का प्रतीक है। जीवंत रंग और सुगंध प्रकृति की सुंदरता और पृथ्वी के कायाकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ समुदाय ऐसे जुलूस भी आयोजित करते हैं जिनमें फूलों और फलों की टोकरियाँ ले जाई जाती हैं, जो मौसम की प्रचुरता का जश्न मनाते हैं।

यहूदी जीवन में टोरा का महत्व

शवोत यहूदी जीवन में टोरा की केंद्रीय भूमिका की याद दिलाता है। यह दिव्य ज्ञान और नैतिक सिद्धांतों को देने का स्मरण करता है जो व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। त्योहार ज्ञान के उपहार और टोरा की शिक्षाओं के लिए प्रतिबिंब, अध्ययन और कृतज्ञता का अवसर प्रदान करता है।

पंच कर्म संकल्प :

स्थायी समुद्री प्रथाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास में, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित शिपिंग और बंदरगाहों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पांच प्रमुख घोषणाएं कीं। मुन्नार के शांत वातावरण में आयोजित मंत्रालय के दूसरे चिंतन शिविर के दौरान ये घोषणाएं की गईं।

प्रमुख घोषणाएँ और 'पंच कर्म संकल्प'

चिंतन शिविर के दौरान, सर्बानंद सोनोवाल ने 'पंच कर्म संकल्प' का अनावरण किया, जो मंत्रालय द्वारा की गई पांच प्रमुख घोषणाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इन घोषणाओं का उद्देश्य समुद्री उद्योग में क्रांति लाना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत टग की खरीद

ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम के तहत, चार प्रमुख बंदरगाह, अर्थात् जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वीओ चिदंबरनार पोर्ट, पारादीप पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट, कांडला प्रत्येक दो टग खरीदेंगे। यह कदम ग्रीन शिपिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में योगदान देगा।

हरित हाइड्रोजन हब का विकास

दीनदयाल पोर्ट और वीओ चिदंबरनार पोर्ट, तूतीकोरिन को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया गया है। यह रणनीतिक पहल इन बंदरगाहों के भीतर पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन के विकास और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो स्थिरता के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी।

नदी और समुद्री क्रूज की सुविधा और निगरानी

मंत्रालय ने एकल खिड़की पोर्टल की स्थापना की घोषणा की, जो नदी और समुद्री यात्राओं की सुविधा और निगरानी के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इस डिजिटल पोर्टल का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, दक्षता में वृद्धि करना और क्रूज ऑपरेटरों और यात्रियों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करना है।

स्मार्ट बंदरगाहों में परिवर्तन

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और वीओ चिदंबरनार पोर्ट, तूतीकोरिन, अगले साल तक स्मार्ट पोर्ट बनने के लिए तैयार हैं। उन्नत तकनीकों, स्वचालन और डिजिटलीकरण के एकीकरण के माध्यम से, ये बंदरगाह अपनी परिचालन दक्षता, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाएंगे।

आईडब्ल्यूटी में कार्गो संचलन और वृद्धि

2014-15 में 74 एमएमटीपीए की तुलना में 2022-23 में कार्गो मूवमेंट 151 एमएमटीपीए तक पहुंचने के साथ तटीय शिपिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसी तरह, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (IWT) के माध्यम से कार्गो हैंडलिंग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो 2014 में 30 एमटीपीए से बढ़कर 2022-23 में 126 एमटीपीए हो गई है। ये आंकड़े तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए की गई विभिन्न पहलों के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं।

जीआरएसई की 'GAINS' स्टार्टअप चुनौती

हाल के दिनों में, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड ने जहाज निर्माण में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। GAINS 2023 नामक अपनी पहल के शुभारंभ के साथ, GRSE का लक्ष्य स्टार्टअप्स की क्षमता का दोहन करना और जहाज डिजाइन और निर्माण उद्योग में नवीन समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करना है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) को श्रेणी 1 मिनी रत्न कंपनी और भारत के प्रमुख रक्षा शिपयार्डों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। 1960 में डीपीएसयू (डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) के रूप में इसकी स्थापना से इसका एक समृद्ध इतिहास है। 1961 में, जीआरएसई ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी युद्धपोत, आईएनएस अजय सौंपकर एक उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया। इस शुरुआती सफलता ने जीआरएसई के लिए भारत और वैश्विक बाजार दोनों में जहाज निर्माण में एक अग्रणी नाम बनने के लिए मंच तैयार किया।

लाभ 2023 पहल

जीआरएसई का नवीनतम प्रयास, गेन 2023 (जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना - 2023) पहल, जहाज निर्माण में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है। इसका उद्देश्य

जहाज डिजाइन और निर्माण उद्योग में पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाना और वर्तमान और उभरती चुनौतियों का समाधान करना है।

श्री जी सूर्य प्रकाश, सहायक प्रबंधक (वित्त) और जीआरएसई के सबसे कम उम्र के अधिकारी, को गेन 2023 पहल शुरू करने का सम्मान मिला। लॉन्च कोलकाता में हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर की उपस्थिति में इसकी शोभा बढ़ाई गई।

लाभ 2023 चुनौती के फोकस क्षेत्र

GAINS 2023 चैलेंज को जहाज निर्माण उद्योग में नवाचार और नए दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस चुनौती के लिए प्राथमिक फोकस क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल/ग्रीन एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी और एफिशिएंसी इनहांसमेंट हैं। इन विषयगत क्षेत्रों पर जोर देकर, जीआरएसई का उद्देश्य जहाज निर्माण में स्थायी प्रथाओं और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है।

GAINS 2023 चैलेंज एक दो चरणों वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विचारों की अधिकता उत्पन्न करना और सबसे आशाजनक विचारों का पोषण करना है। पहले चरण में, प्रतिभागियों को संक्षिप्त सचित्र और लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, साथ ही लागत का एक मोटा क्रम और पेशेवर योग्यता का औचित्य।

रय्याना बरनावी

रय्याना बरनावी ने अंतरिक्ष में उद्यम करने वाली पहली अरब महिला के रूप में इतिहास रचा। सऊदी अरब का बहुप्रतीक्षित पहला अंतरिक्ष मिशन 21 मई को हुआ। बरनावी ने अपने सह-अंतरिक्ष यात्री अली अल-क़रनी के साथ, स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर अपनी यात्रा शुरू की।

प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन और जॉन शॉफनर इस महत्वपूर्ण मिशन पर बरनावी और अल-कर्नी में शामिल हुए। साथ में, उन्होंने सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक टीम बनाई।

मिशन ने सऊदी अरब के लिए बहुत महत्व रखा क्योंकि यह विजन 2030 सुधार कार्यक्रम के साथ संरेखण में अपनी अंतरिक्ष विज्ञान शिक्षा का विस्तार करने और तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए प्रयासरत था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक विविधीकरण को चलाते हुए युवा सउदी के लिए नए अवसर और रोजगार सृजित करना था।

आईएसएस के मिशन का प्राथमिक उद्देश्य प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित करना था। टीम ने अंतरिक्ष स्टेशन के अद्वितीय माइक्रोग्रैविटी वातावरण में मानव अनुसंधान, कोशिका विज्ञान और क्लाउड सीडिंग प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित किया। इन प्रयोगों ने वैज्ञानिक प्रगति में योगदान दिया और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया।

अंतरिक्ष में सऊदी अरब का इतिहास

अंतरिक्ष अन्वेषण में सऊदी अरब की भागीदारी 1985 में वापस आ गई जब प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद, एक प्रतिष्ठित वायु सेना पायलट, ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित अंतरिक्ष यात्रा में भाग लिया। तब से, देश इस क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा था।

यूएई से हज्जा अल-मंसूरी जैसे पिछले अरब अंतरिक्ष यात्रियों की सफलता पर निर्माण, जो आईएसएस तक पहुंचने वाले पहले अरब बने, सऊदी अरब के मिशन ने क्षेत्र के अंतरिक्ष प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया।

दीर्घकालीन आईएसएस सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, रूस और पश्चिम के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जो 1998 से लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे (17,400 मील प्रति घंटे) की आश्चर्यजनक गति से लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। लंबे समय से चली आ रही इस वैज्ञानिक चौकी ने एक अद्वितीय प्रदान किया। अनुसंधान, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मंच।

हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय

हिरोशिमा, जापान में स्थित, हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई विनाशकारी परमाणु बमबारी की याद दिलाता है। अगस्त 1955 में स्थापित, संग्रहालय हिरोशिमा की परमाणु बमबारी की घटनाओं और परिणामों के दस्तावेजीकरण के लिए एक समर्पित स्थान के रूप में कार्य करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य नेताओं के साथ इस संग्रहालय का दौरा किया था।

शांति स्मारक संग्रहालय का संग्रह हिरोशिमा में हुई त्रासदी का मार्मिक प्रमाण है। पीड़ितों द्वारा छोड़े गए सामान, तस्वीरें और अन्य सामग्री परमाणु बमबारी की भयावहता की एक झलक पेश करते हैं। प्रदर्शन पर प्रत्येक वस्तु वास्तविक लोगों के दुःख, क्रोध और दर्द का प्रतिनिधित्व करती है, यह सुनिश्चित करती है कि उनकी कहानियों को कभी भुलाया न जाए।

गहन समझ के लिए विभाजित

1994 में, संग्रहालय का जीर्णोद्धार हुआ, जिसके कारण इसका विभाजन दो खंडों में हुआ: ईस्ट विंग और वेस्ट विंग। ईस्ट विंग एक व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करता है, हिरोशिमा के इतिहास, बम गिराने का निर्णय, बमबारी के दौरान और बाद में नागरिकों के जीवन, और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए चल रहे प्रयासों में तल्लीन करता है। वेस्ट विंग, मूल संग्रहालय का हिस्सा, बम के भौतिक और मानव टोल पर ध्यान केंद्रित करता है, जो गर्मी की किरणों, विस्फोट और विकिरण प्रभावों से होने वाले नुकसान को उजागर करता है।

नवीनीकरण की यात्रा

2014 में, हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय ने एक प्रमुख नवीनीकरण परियोजना शुरू की। ईस्ट विंग अप्रैल 2017 में फिर से खुल गया, और अधिक इंटरएक्टिव डिस्प्ले और बम विस्फोट के प्रभावों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्शन मैपिंग का उपयोग करने वाला एक नया मॉडल पेश किया। इस अवधि के दौरान प्रदर्शनों को भी ताज़ा किया गया, जिसमें पीड़ितों के व्यक्तिगत सामान पर ज़ोर दिया गया और उनके स्थायी प्रभाव को प्रदर्शित किया गया।

वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक

हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय का महत्व इसकी दीवारों से परे है। जब सात के समूह (जी-7) के नेताओं ने संग्रहालय का अभूतपूर्व संयुक्त दौरा किया तो यह उम्मीद की किरण बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य परमाणु शक्तियों के नेताओं ने ऐसे हथियारों के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में संग्रहालय की भूमिका को स्वीकार करते हुए, परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन 2023

पापुआ न्यू गिनी में आयोजित फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) शिखर सम्मेलन ने व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। 2014 में स्थापित इस बहुराष्ट्रीय समूह का उद्देश्य भारत और 14 प्रशांत द्वीप समूह देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नीयू, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, शामिल हैं। तुवालू और वानुअतु।

इस वर्ष के FIPIC शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं में से एक सभी 14 देशों के नेताओं की पूर्ण भागीदारी थी। कनेक्टिविटी और इन देशों के सामने आने वाली अन्य चुनौतियों के कारण यह एक दुर्लभ घटना थी। इन देशों के अभिसरण ने भारत और प्रशांत क्षेत्र के बीच संबंधों को मजबूत करने के महत्व और क्षमता को रेखांकित किया।

उज्जवल भविष्य के लिए संबंधों को मजबूत करना

FIPIC शिखर सम्मेलन ने भारत और प्रशांत द्वीप समूह देशों के बीच सहयोग और संवाद के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान किया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ, सहयोग और विकास को बढ़ाना है। व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर चर्चा के माध्यम से नेताओं ने उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत साझेदारी बनाने की दिशा में काम किया।

अनुच्छेद 239AA क्या है?

संविधान का अनुच्छेद 239AA दिल्ली की विशेष स्थिति और शासन संरचना को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। अनुच्छेद 239AA की व्याख्या करने वाले हाल के SC के फैसले को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने की मांग करने वाले अध्यादेश के पारित होने के साथ रद्द कर दिया गया था।

1991 में 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239AA को संविधान में जोड़ा गया था। इसने एस बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया। प्रावधान दिल्ली को विशिष्ट शक्तियों और सीमाओं के साथ एक प्रशासक और एक विधान सभा प्रदान करता है।

विधान सभा की शक्तियाँ

अनुच्छेद 239AA के अनुसार, दिल्ली की विधान सभा को पूरे शहर या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है। विधायी अधिकार पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची या समवर्ती सूची के मामलों तक विस्तृत है। यह प्रावधान विधानसभा को अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ हद तक विधायी स्वायत्तता प्रदान करता है।

संघवाद और दिल्ली की स्थिति

2018 में संविधान पीठ के फैसले ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, संघवाद की अवधारणा इस पर लागू होती है। इस फैसले ने दिल्ली के शासन में सहकारी संघवाद के महत्व को पहचाना, शहर के प्रशासन की अनूठी प्रकृति पर प्रकाश डाला।

कार्यकारी शक्ति और केंद्र की भूमिका

दिल्ली में पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था पर कार्यकारी शक्ति केंद्र (भारत संघ) के पास है। जबकि विधान सभा के पास विधायी अधिकार हैं, केंद्र इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष कार्यकारी नियंत्रण रखता है। सत्ता का यह विभाजन क्षेत्रीय प्रशासन और केंद्रीय निरीक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 239एए के प्रावधान में कहा गया है कि उपराज्यपाल (एलजी) और मंत्रियों के बीच मतभेद के मामले में, मामला निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि विवादों को एक उचित संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाता है, जिसमें अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के पास होता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सीमाएं

दिल्ली की एनसीटी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) सरकार संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं के भीतर काम करती है। जबकि इसके पास कुछ हद तक स्वतंत्रता और विधायी शक्ति है, इसके कार्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि क्षेत्रीय सरकार संवैधानिक योजना के ढांचे के भीतर काम करती है।

सहभागी शासन पर जोर

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के अलग फैसले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 239AA भागीदारी, प्रतिनिधि और उत्तरदायी सरकार के आधार पर संस्थागत शासन प्रदान करता है। यह जोर दिल्ली के शासन ढांचे में अंतर्निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है।

सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत फैसला

11 मई को, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा एक सर्वसम्मत फैसले ने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच सत्ता की लड़ाई को संबोधित किया। सत्तारूढ़ ने एनसीटीडी के प्रशासन में भारत संघ की सीमित भागीदारी को रेखांकित करते हुए अनुच्छेद 239AA द्वारा स्थापित संघीय मॉडल को दोहराया।

यूक्रेन संघर्ष में बखमुत

यूक्रेन का बखमुत शहर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया है। हाल की घटनाओं ने विवादित दावों और सामरिक विचारों के साथ बखमुट की स्थिति और महत्व पर ध्यान दिया है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमिर ज़ेलेंस्की ने भाड़े के वैगनर समूह और रूस द्वारा बखमुत पर कब्जा करने के दावों का दृढ़ता से खंडन किया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अनुसार, शहर पर रूसी संघ का कब्जा नहीं है। यह बयान वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन द्वारा की गई पहले की घोषणा का खंडन करता है, जिन्होंने रूसी सेनाओं द्वारा बखमुत पर कब्जा करने की घोषणा की थी।

बखमुत का प्रतीकात्मक महत्व

हालांकि उद्योग या स्थान के संदर्भ में बखमुत का महत्वपूर्ण रणनीतिक मूल्य नहीं है, लेकिन इसके प्रतीकात्मक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विश्लेषकों का सुझाव है कि रूस ने महीनों के सैन्य अभियानों के बाद मुख्य रूप से एक बहुत जरूरी जीत हासिल करने के लिए बखमुत को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना। इसके अतिरिक्त, रूसी सेना के भीतर एक प्रतिस्पर्धी गतिशील ने बखमुत को लक्षित करने के निर्णय में योगदान दिया।

रणनीतिक विचार और महत्वपूर्ण सड़कों से निकटता

कई महत्वपूर्ण सड़कों से बखमुत की निकटता रूसी प्रगति के लिए कुछ रणनीतिक मूल्य प्रदान करती है। इन मार्गों पर नियंत्रण संभावित रूप से इस क्षेत्र में रूसी आंदोलनों को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि यह पहलू बखमुत के महत्व की प्रतीकात्मक प्रकृति पर जोर देते हुए क्षेत्र के कई कस्बों पर लागू होता है।

यूक्रेनी परिप्रेक्ष्य: मास्को के सैनिकों को पहनना

यूक्रेनियन लोगों के लिए, बखमुत पर लड़ाई को मास्को के सैनिकों को कमजोर करने और उनकी आपूर्ति को कम करने के साधन के रूप में देखा गया है। रूसी सेना को हर ब्लॉक के लिए लड़ने के लिए मजबूर करके, यूक्रेनियन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने और मास्को की आक्रामक क्षमताओं में बाधा डालने का लक्ष्य रखा। बखमुत पर लंबा संघर्ष रूसी सैन्य अभियानों को समाप्त करने और बाधित करने की यूक्रेन की रणनीति का हिस्सा रहा है।

संभावित प्रभाव और भविष्य के लक्ष्य

यदि रूसी सेना ने वास्तव में बखमुत पर कब्जा कर लिया है, तो यह आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी के रूप में काम कर सकता है। दोनेत्स्क क्षेत्र के दो बड़े शहर क्रामटोरस्क और स्लोवियांस्क अगले लक्ष्य हो सकते हैं। मॉस्को का लक्ष्य इन शहरों पर नियंत्रण हासिल करके "पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क" की "मुक्ति" के रूप में संदर्भित निष्कर्ष निकालना है। इसके अतिरिक्त, बखमुत का नियंत्रण शहर के पश्चिम में पास के शहर चासिव यार की ओर बढ़ने में सहायता कर सकता है।

ई-अपील योजना 2023

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में "ई अपील" योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) डिफ़ॉल्ट और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) से संबंधित लंबित अपीलों के मुद्दे को संबोधित करना है। इस नई पहल से अपील प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और ऐसे मामलों के समाधान में तेजी लाने की उम्मीद है।

"ई अपील" योजना के तहत, संयुक्त आयुक्त (अपील) को उनके समक्ष दाखिल या उन्हें आवंटित/स्थानांतरित अपीलों के निपटान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके पास कारण बताओ नोटिस भेजने और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंड शुरू करने की शक्ति है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनके पास सम्मन जारी करने का अधिकार नहीं है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई का आयोजन

एक निर्बाध अपील प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, अपीलों की व्यक्तिगत सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। यह दृष्टिकोण न केवल समय और संसाधनों को बचाता है बल्कि इसमें शामिल पक्षों के बीच प्रभावी संचार को भी सक्षम बनाता है। यह अपील की कार्यवाही में सुविधा और दक्षता को बढ़ावा देता है।

आयकर अधिनियम में संशोधन

इस योजना को समायोजित करने के लिए, "नए संयुक्त आयुक्त (अपील)" के पदनाम को शामिल करने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह संशोधन ढांचे को मजबूत करता है और अपीलों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए एक समर्पित प्राधिकरण प्रदान करता है।

संयुक्त आयुक्तों की तैनाती

"ई अपील" योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, सीबीडीटी ने आयकर विभाग से संयुक्त आयुक्तों के लगभग 100 पदों को तैनात करने की योजना बनाई है। ये अधिकारी संयुक्त आयुक्त (अपील) के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जा सके और अपीलों का समय पर समाधान किया जा सके।

टीडीएस डिफॉल्ट और रिटर्न ऑफ इनकम की प्रोसेसिंग पर फोकस

"ई अपील" योजना मुख्य रूप से टीडीएस डिफॉल्ट से संबंधित अपील, टीडीएस डिफॉल्ट पर आदेश और आय की वापसी के प्रसंस्करण पर आदेश पर ध्यान केंद्रित करती है। इन विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करके, योजना का उद्देश्य प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना और इन श्रेणियों में लंबित अपीलों को कम करना है।

पेंडेंसी कम करना और दक्षता बढ़ाना

"ई अपील" योजना की शुरूआत कर प्रशासन प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। अपील प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करके, यह योजना कर संबंधी मामलों के अधिक प्रभावी और समय पर समाधान में योगदान देती है।

नमो शेतकरी महासंमान योजना

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य में किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई वित्तीय योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नमो शेतकरी महासंमन योजना के नाम से जानी जाने वाली इस योजना को मंजूरी दी गई।

नमो शेतकरी महासंमन योजना के तहत, महाराष्ट्र में किसानों को 6,000 रुपये का वार्षिक भुगतान प्राप्त होगा। यह वित्तीय सहायता 6,000 रुपये की उस राशि के अतिरिक्त है जो किसानों को केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रति वर्ष किश्तों में पहले से ही प्राप्त होती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को अतिरिक्त बढ़ावा देना और उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है।

लाभार्थी और स्वीकृति

महाराष्ट्र में एक करोड़ से अधिक किसानों को राज्य सरकार की नमो शेतकरी महासंमान योजना से लाभ होने की उम्मीद है। यह पहल कृषि समुदाय का समर्थन करने और उनके समग्र कल्याण में सुधार के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

बजट में की गई पहल की घोषणा

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो राज्य के वित्त मंत्री के रूप में भी काम करते हैं, ने शुरू में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में नमो शेतकरी महासम्मान योजना की घोषणा की थी। बजट में इस योजना को शामिल करना किसानों

के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

किसानों की आजीविका का समर्थन करना

नमो शेतकारी महासंमान योजना के शुभारंभ के साथ, महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य किसानों के सामने आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना और उनकी आर्थिक भलाई को बढ़ावा देना है। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करके, इस योजना का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और उन्हें चुनौतियों से पार पाने और अपनी कृषि गतिविधियों में निवेश करने में सक्षम बनाना है।

इराक के विकास का मार्ग

इराक अपनी सड़क और रेल अवसंरचना में पर्याप्त सुधार के माध्यम से खुद को एक प्रमुख क्षेत्रीय परिवहन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक साहसिक पहल कर रहा है। परियोजना, जिसे "विकास के मार्ग" के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य इराक को पड़ोसी देशों से जोड़ना, आर्थिक एकीकरण और व्यापार को बढ़ावा देना है। प्रधान मंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के नेतृत्व में, यह पहल मौजूदा चुनौतियों को दूर करने और मध्य पूर्व में माल और लोगों की आवाजाही में इराक को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है।

विकास का मार्ग एक विशाल परियोजना है जिसे इराक की पूरी लंबाई में फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें तुर्की के साथ उत्तरी सीमा से दक्षिणी खाड़ी क्षेत्र तक 1,200 किलोमीटर (745 मील) की प्रभावशाली दूरी शामिल है। प्रधान मंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने ईरान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन के दौरान इस महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया।

समय सीमा और सहयोग

जबकि विकास के मार्ग को पूरा करने के लिए व्यापक सहयोग और आगे की चर्चाओं की आवश्यकता होगी, इस स्मारकीय प्रयास के लिए अनुमानित समय सीमा तीन से पांच वर्ष होने का अनुमान है। परियोजना का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों को इसके विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वे अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार विशिष्ट वर्गों में शामिल हो सकें।

इन्फ्रास्ट्रक्चर चुनौतियों पर काबू पाना

इराक के परिवहन क्षेत्र के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक इसका जीर्ण-शीर्ण बुनियादी ढांचा है। देश की सड़कें गड्ढों और अपर्याप्त रखरखाव से ग्रस्त हैं, जिससे कुशल कनेक्टिविटी बाधित होती है। हालाँकि, विकास का मार्ग इराक के परिवहन नेटवर्क के पुनर्निर्माण और उन्नयन में निवेश करके इन मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने का अवसर प्रस्तुत करता है।

खाड़ी और परे से जुड़ना

इराक की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति परिवहन केंद्र बनने के लिए एक अनूठा लाभ प्रस्तुत करती है। खाड़ी क्षेत्र को तुर्की और यूरोप से जोड़कर, विकास मार्ग का उद्देश्य माल और लोगों की आवाजाही के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में इराक की स्थिति की क्षमता का दोहन करना है। परियोजना में अल-फॉ के वाणिज्यिक बंदरगाह पर क्षमता का विस्तार शामिल है, जो समुद्री और भूमि-आधारित परिवहन प्रणालियों के बीच कार्गो के कुशल हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।

ट्रेन स्टेशनों और क्षेत्रीय एकीकरण

विकास के मार्ग के हिस्से के रूप में, लगभग 15 ट्रेन स्टेशनों की योजना मार्ग के साथ बनाई गई है, जो बसरा, बगदाद और मोसुल जैसे प्रमुख शहरों में रणनीतिक रूप से स्थित हैं। ये स्टेशन पूरे क्षेत्र में परिवहन के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण कनेक्टर्स के रूप में काम करेंगे। परियोजना में भाग लेने वाले देशों के बीच अन्योन्याश्रितता को मजबूत करने और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने की कल्पना की गई है।

ड्राइंग समानताएं: द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव

इराक की परिवहन आकांक्षाएं चीन के परिवर्तनकारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समान हैं। जिस तरह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उद्देश्य व्यापक बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों को जोड़ना है, उसी तरह इराक का विकास मार्ग खाड़ी, तुर्की और यूरोप के बीच महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है। दोनों पहलें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का एक साझा लक्ष्य साझा करती हैं।

नया संसद भवन

भारत में नया संसद भवन एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो राष्ट्र के लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है। 28 मई को उद्घाटन किया गया, यह देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती प्राचीन मूर्तियों से प्रेरित जटिल मूर्तियों और रूपांकनों से सुशोभित है।

नए संसद भवन के छह दरवाजों पर, प्राचीन मूर्तियों से प्रेरित मूर्तियाँ केंद्र में हैं। इन राजसी शख्सियतों का गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो राष्ट्र की कल्पना को आकर्षित करती हैं। प्रत्येक दरवाजा अद्वितीय प्रेरणाओं को प्रदर्शित करता है जो विस्मय और प्रशंसा की भावना पैदा करता है।

राजसी गज द्वार

प्रवेश द्वारों में से एक गजद्वार में पत्थर के हाथी लगाए गए हैं जो कर्नाटक के बनवासी में 9वीं शताब्दी के मधुकेश्वर मंदिर में मूर्तियों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये उल्लेखनीय मूर्तियां ताकत और अनुग्रह का प्रतीक हैं।

कृपालु अश्व द्वार

अश्व द्वार के प्रवेश द्वार पर घोड़ों की मूर्तियाँ हैं, जो 13वीं शताब्दी के ओडिशा के सूर्य मंदिर की मूर्तियों की याद दिलाती हैं। ये सुरुचिपूर्ण चित्रण घोड़ों से जुड़ी शक्ति और सुंदरता का प्रतीक हैं।

प्रेरित द्वार

शारदुला, हम्सा और मकर द्वार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्ध मूर्तियों से प्रेरित मूर्तियों को प्रदर्शित करते हैं। ग्वालियर में गूजरी महल, हम्पी में विजय विट्ठल मंदिर और कर्नाटक में होयसलेश्वर मंदिर इन जटिल कृतियों के लिए संग्रहालय का काम करते हैं। प्रत्येक मूर्तिकला का अपना सांस्कृतिक महत्व होता है और नए संसद भवन की भव्यता में इजाफा होता है।

देदीप्यमान गरुड़ द्वार

गरुड़ द्वार, अंतिम प्रवेश द्वार, में विष्णु के पर्वत (वाहन) की मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियां तमिलनाडु की 18वीं शताब्दी सीई नायक काल की मूर्तिकला से प्रेरणा लेती हैं। गरुड़ द्वार श्रद्धा और आध्यात्मिकता की भावना का परिचय देता है।

फौकॉल्ट के पेंडुलम का प्रतीकवाद

संविधान हॉल की त्रिकोणीय छत के भीतर, फौकॉल्ट का पेंडुलम एक बड़े रोशनदान से सुंदर ढंग से लटका हुआ है। यह मनोरम स्थापना पृथ्वी के घूर्णन का प्रतीक है और भारत और ब्रह्मांड के बीच सद्भाव का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमारी दुनिया के परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है।

कमल और मयूर अंदरूनी

राज्यसभा, उच्च सदन का आंतरिक डिजाइन, भारत के राष्ट्रीय फूल, कमल से प्रेरणा लेता है। यह प्रतीकात्मक रूप कक्ष के भीतर एक शांत और चिंतनशील वातावरण बनाता है। दूसरी ओर, लोकसभा का आंतरिक भाग, निचला सदन, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरणा लेता है। जीवंत रंग और जटिल पैटर्न गर्व और जीवन शक्ति की भावना पैदा करते हैं।

सेरेमोनियल फ़ोयर और सांस्कृतिक प्रतीक

नए संसद भवन में तीन औपचारिक फ़ोयर हैं जो प्रभावशाली पीतल की छवियों को प्रदर्शित करते हैं। इन शानदार टुकड़ों में महात्मा गांधी, चाणक्य, गार्गी, सरदार वल्लभभाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, और कोणार्क के सूर्य मंदिर से रथ का पहिया। वे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र के लिए इन सम्मानित व्यक्तियों के योगदान के लिए एक वसीयतनामा के रूप में काम करते हैं।

75 रुपये का स्मारक सिक्का

25 मई को जारी एक अधिसूचना में, वित्त मंत्रालय ने एक नया स्मारक सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की। यह सिक्का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य रखता है, देश की विरासत में महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तित्वों का जश्न मनाता है।

75 रुपये के स्मारक सिक्के की संरचना

नया पेश किया गया 75 रुपये का स्मारक सिक्का एक अद्वितीय चतुर्धातुक मिश्र धातु से बना है। इसमें 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता होता है। धातुओं का यह मिश्रण टिकाउपन और दीर्घायु सुनिश्चित करता है, जिससे सिक्का संग्राहकों और उत्साही लोगों के लिए समान रूप से एक प्यारा टुकड़ा बन जाता है।

डिजाइन और शिलालेख

सिक्के का अग्र भाग मध्य में अशोक स्तंभ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष से सुशोभित है। प्रतीक के नीचे शिलालेख "सत्यमेव जयते" (सत्यमेव जयते) सुरुचिपूर्ण ढंग से उत्कीर्ण है। बायीं परिधि पर, शब्द "भारत" (भारत) देवनागरी लिपि में खुदा हुआ है, जबकि अंग्रेजी में दायीं परिधि पर "इंडिया" शब्द अंकित है।

सिक्का उछालने से देश की लोकतांत्रिक भावना का प्रदर्शन करते हुए, नए संसद भवन की मनोरम छवि का पता चलता है। ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में "संसद संकुल" शिलालेख है, जबकि निचली परिधि गर्व से अंग्रेजी में "पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स" शब्द प्रदर्शित करती है।

स्मारक सिक्के प्राप्त करना

स्मारक सिक्के प्राप्त करने में रुचि रखने वालों के लिए, सिक्योरिटीज ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) वेबसाइट एक विश्वसनीय मंच के रूप में कार्य करती है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्मारक सिक्कों का मूल्य हमेशा उनके अंकित मूल्य के साथ संरेखित नहीं हो सकता है। इन सिक्कों में अक्सर चांदी या सोने जैसी कीमती धातुएँ होती हैं, जो उन्हें उनके मौद्रिक मूल्य से परे आंतरिक मूल्य के साथ संग्रहणीय बनाती हैं।

केंद्र सरकार और आरबीआई की भूमिका

कॉइनेज एक्ट, 2011 द्वारा दिए गए अधिकार के तहत, केंद्र सरकार के पास विभिन्न संप्रदायों में सिक्कों को डिजाइन करने और बनाने की शक्ति है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इन सिक्कों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे केंद्र सरकार के इरादे से जनता तक पहुँचें।

भारत भर में टकसाल

स्मारक सहित सभी सिक्के, भारत सरकार के स्वामित्व वाली चार टकसालों में ढाले जाते हैं। ये टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित हैं। वे मुद्रा की अखंडता को संरक्षित करते हुए, देश के सिक्कों के उत्पादन के पीछे सटीकता और शिल्प कौशल के लिए जिम्मेदार हैं।

One liner:-

- भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरत्न रूस में एक बड़े अपग्रेड से गुजरी और 97 दिनों तक चलने के बाद मुंबई पहुंची।
- खांसी की दवाई के निर्यातकों को 1 जून से निर्दिष्ट सरकारी प्रयोगशालाओं में अपने उत्पादों का परीक्षण करना होगा।
- शिक्षा मंत्रालय ने 60 स्कूल बोर्डों को एकजुट करने के उद्देश्य से पारख पर बैठक आयोजित की।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ई-सिगरेट के निर्माण, बिक्री और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करता है।
- केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्रालय ने 'शिक्षा पुरस्कार' और 'हिंदी भाषा हिंदी लेखक पुरस्कार' पुरस्कार बंद कर दिए हैं।
- देश भर के बैंक एक्सचेंज के लिए 2,000 रुपये के नोट स्वीकार करना शुरू कर देंगे।
- टीसीएस के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को बीएसएनएल का 15,000 करोड़ रुपये का 4जी ऑर्डर मिला।
- ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मजबूत शासन के लिए जोर देता है।
- ओएनडीसी नेटवर्क भागीदारों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अकादमी शुरू करने के लिए तैयार है।
- ईयू ने मेटा पर लगाया 1.3 अरब डॉलर का जुर्माना, अमेरिका को डेटा भेजने से रोकने का आदेश
- चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए
- पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पहुंची।
- बर्ड फ्लू: ब्राजील में कई मामले सामने आने के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित
- चेन्नई जून में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा।